



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229]  
No. 229]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 1997/चैत्र 17, 1919  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 1997/CHAITRA 17, 1919

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

**का० आ० 301(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवेदन करने पर उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की बाबत अधिस्थगन आदेश दिया है;

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में समामेलन करने के लिए एक स्कीम तैयार की है;

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उपधारा (6) के उपबन्धों के अनुसार संबंधित बैंकों को उक्त स्कीम का प्रारूप भेजने के पश्चात् और उक्त स्कीम की बाबत प्राप्त आरोपों और आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् उक्त स्कीम को संशोधित किया है और उसे मंजूरी के लिए, केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबंधन और शर्तों पर और उनके अधीन रहते हुए उक्त स्कीम को मंजूरी देती है।

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ समामेलन) स्कीम; 1997 है।
- (2) यह उस तारीख को (इसके पश्चात् विहित तारीख के रूप में संदर्भित) प्रवृत्त होगी जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय—2

कारबार, संपत्तियों, आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण

2. आस्तियों और दायित्वों का अंतरण और उनका साधारण प्रभाव :

- (1) विहित तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करेगी (इसके पश्चात् विहित तारीख के रूप में संदर्भित) अंतरक बैंक सभी अधिकार, शक्तियां, दावे, मांगें, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार, फायदे, आस्तियां और परिसंपत्तियां, जंगम और स्थावर, जिसमें स्थान सम्मिलित है जो भूधृति की सभी अनुबंधितियों और जिसे पट्टे करार के अंतर्गत उन्हें धारित किया गया है, उसमें निहित किराये की रकम तथा अन्य रकम औचित्यों के अधीन है तथा कार्यालय के फर्नीचर, खुले रखे गए उपस्कर, संयंत्र, साधित्र और साधन, बहियां, कागज, लेखन सामग्री का भंडार, अन्य भंडार और भंडारण स्टॉक शेयर और प्रतिभूतियां, हाथ में प्राप्य और संव्यवहार में सभी बिल, हाथ में सभी नकदी और चालू अथवा निक्षेप

खाते (जिसमें मांग पर या संक्षिप्त सूचना पर धन सम्मिलित हैं) में समस्त नकदी जिसमें बैंक का सोना, चांदी, सभी बही ऋण, बंधक ऋण और प्रतिभूति के फायदे सहित अन्य ऋण और इसकी गारंटी, यदि कोई हो, संपत्ति अधिकार और आस्तियां यदि कोई हो, अंतरक बैंक के कारबार के संबंध में सभी गारंटियां इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन अंतरित मानी जाएंगी तथा वे उसकी संपत्तियां और आस्तियां होंगी और निर्धारित तारीख से अंतरक बैंक के सभी दायित्व, शुल्क और उन्मोचन यहां दी गई और अंतरिती बैंक के दायित्व, शुल्क और बाध्यताएं होंगी;

(2) पूर्वगामी उपबंधों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार, मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटॉर्नी), विधि प्रतिनिधित्व की मंजूरियां तथा अन्य लिखित वे किसी भी स्वरूप के हों अथवा नियत तारीख से तुरन्त पहले प्रभावी हों, आगे बताई गई सीमा तक और ढंग से अंतरिती बैंक के विरुद्ध या पक्ष में प्रभावी होंगे और उन पर इस तरह कार्यवाहियां की जाएंगी, मानो अन्तरक बैंक के बजाय अंतरिती बैंक उसका एक पक्षकार हो अथवा मानो अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी किए गए हों।

(3) यदि विहित तारीख को कोई वाद अपील अथवा किसी भी तरह की कोई अन्य विधिक प्रक्रिया अन्तरक बैंक के द्वारा या विरुद्ध कोई अन्य प्रक्रिया लम्बित है तो उसे उपशमित या रोका नहीं जाएगा या उसका किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु यह इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तरिती बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध अभियोजित की जाएगी और प्रवृत्त बनी रहेगी।

(4) यदि भारत के बाहर किसी देश की विधि के अनुसार इस स्कीम के उपबंध उस देश में स्थित किसी आस्ति या दायित्वों जो अंतरक बैंक के अंतरिती बैंक को दिये गये वचन का भाग है, के अन्तरण अथवा उसको निहित करने के लिए स्वयं के प्रभाव में हों तो वे अंतरिती बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपे हुए माने जाएंगे और मुख्य कार्यपालक अधिकारी उसके परिचालनों को बंद करने के प्रयोजन के लिए सभी शक्तियों का उसी प्रकार प्रयोग करेगा जैसी कि वे अन्तरक बैंक द्वारा प्रयोग की गई हों। मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार के अन्तरण को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगा जो भारत के बाहर उस देश के कानून द्वारा अपेक्षित हो और उसके संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अंतरक बैंक की किसी भी आस्ति की वसूली करेगा अथवा उसके दायित्वों का उन्मोचन करेगा और उसके शुद्ध आगमनों को अंतरिती बैंक को अंतरित करेगा।

3. अन्तरक बैंक की बहियों को बंद करना और तुलनपत्र को तैयार करना :

(1) अन्तरक बैंक की बहियों को बंद किया जाएगा और 30-9-1996 को कारबार के बंद होने पर, प्रथम दृष्टांत रूप में उसका तुलन किया जाएगा और तुलनपत्र तैयार किया जाएगा तथा तुलनपत्र, चार्टर्ड एकाउंटेंट या इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित या नामित चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म द्वारा संपरीक्षित और प्रमाणित किया जाएगा।

(2) पूर्वगामी पैरा के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई अंतरक बैंक के तुलन पत्र की एक प्रति अंतरक बैंक के तुलन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र अंतरक बैंक द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी और यथाशीघ्र इसके प्राप्त होने के पश्चात् अंतरक बैंक का तुलन पत्र या लाभ और हानि खातों अथवा उसके सदस्यों को प्रस्तुत करने अथवा कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने अथवा तुलन पत्र और खातों पर विचार करने के प्रयोजन के लिए वार्षिक साधारण अधिवेशन करने अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अनुसार विहित प्रयोजन का अनुपालन करने की अपेक्षा नहीं रहेगी और इसके पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 285 द्वारा यथा अपेक्षित अंतरक बैंक के निदेशक मंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4. आस्तियों का मूल्यांकन और दायित्वों का अवधारण :

अंतरिती बैंक अंतरक बैंक के परामर्श से संपत्ति और आस्तियों का मूल्यांकन करेगा और उसके दायित्वों का आकलन निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार करेगा, अर्थात्

(1)(क) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न अन्य निवेश का विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान बाजार दरों पर मूल्यांकन किया जाएगा।

(ख)(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना में दिये गये सिद्धांतों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निर्धारित तारीख से ठीक पहले दिन की स्थिति में किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार की वे प्रतिभूतियां जैसे डाकघर प्रमाणपत्र, खजाना जमा बचत प्रमाणपत्रों और अल्प बचत योजना के अधीन जारी बचत निक्षेप प्रमाणपत्र या कोई अन्य प्रतिभूति या प्रमाणपत्र का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य या उस तारीख के नकदीकरण मूल्य जो उच्चतर हो, पर किया जाएगा।

(iii) जहां जमींदारी उन्मूलन बंधपत्र जैसी किसी सरकारी प्रतिभूति अथवा इस प्रकार की कोई अन्य प्रतिभूति, जिसकी बाबत संदाय किस्तों में किया जाना है, के बाजार मूल्य का अभिनिश्चय नहीं किया जाना है, किसी कारण के लिए, उस प्रतिभूति का मूल्यांकन मूलधन की किस्तों और अदा करने के लिए शेष ब्याज इसकी किस्तों के देय रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए उचित समझी गयी रकम पर किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस सरकार की प्रतिभूति नहीं है उस सरकार द्वारा जारी की गई उसी अवधि के अथवा लगभग उसी अवधि की किसी प्रतिभूति पर प्राप्य रकम कितनी है अन्य सुसंगत बातों का भी ध्यान रखा जाएगा।

(ग) जहां किसी प्रतिभूति, अंश, डिबेंचर, बंधपत्र या अन्य निवेश का बाजार मूल्य असामान्य कारकों द्वारा प्रभावित होने वाले कारण द्वारा विचार किया जाता है वहां किसी न्यायोचित अवधि पर इसके औसत बाजार के आधार पर निवेश का मूल्यांकन किया जाएगा।

(घ) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर (अंश), डिबेंचर, बंधपत्र या कोई अन्य निवेश, अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है, वहां केवल ऐसे मूल्य को, यदि कोई हो, गणना में लिया जावेगा जो जारीकर्ता समनुषंगी की वित्तीय स्थिति, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान इसके द्वारा संदत्त लाभांश और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित समझी गई है।

(ङ) स्थान और सभी अन्य स्थावर संपत्तियों और दावों के समाधान में अर्जित आस्तियां उनके बाजार मूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी।

(च) फनीचर और फिक्सचर, स्टॉक में लेखन सामग्री और अन्य आस्तियां, यदि कोई हों, प्रतियों के अनुसार लिखे गए मूल्य या उचित समझे जा सकने वाले वसूलीय मूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी।

(छ) अग्रिम, जिसमें विक्रय किये गये बिल, बट्टा बही तथा अन्य आस्तियों की समीक्षा अंतरिती बैंक और प्रतिभूतियों द्वारा की जाएगी, जिसमें इसके लिए अंतरिती बैंक द्वारा परीक्षित सत्यापित की जाने वाली धारित गारंटियां हैं, तत्पश्चात् अग्रिमों को जिसमें उसके भाग भी हैं दो प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात् "अच्छा समझे गये अग्रिम और तत्पर वसूली" तथा "तत्पर वसूली के लिए विचार न किये गये अग्रिम और/या दूबंत या संदेहास्पद वसूली"।

(2) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए दायित्वों में ऐसे सभी आकस्मिक दायित्व सम्मिलित होंगे जिन्हें अंतरिती बैंक विहित तारीख को या उसके पश्चात् अपने संसाधनों से पूरा करने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित करे।

(3) (i) जहां विहित तारीख को किसी आस्ति का मूल्यांकन अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहां यह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात् तारीख को भागतः या पूर्णतः वसूलनीय आस्ति के रूप में समझी जाएगी।

(ii) आस्ति के मूल्यांकन और/या किसी अग्रिम और/या दायित्व के अवधारण के बारे में अंतरिती बैंक और अंतरक बैंक में किसी असहमति की दशा में यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक की राय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा परन्तु यह कि जब तक कि कोई इस तरह की राय प्राप्त नहीं हो जाती है, अंतरिती बैंक द्वारा मद या उसके भाग के मूल्यांकन को इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अन्तिम रूप से अपनाया जाएगा,

(iii) यदि ऐसा करना आवश्यक दशा में हो तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ऐसी मदों के मूल्यांकन के संबंध में जैसा वह उचित समझे, तकनीकी सलाह लेना सक्षम होगा, जो वह आस्तियों की किसी ऐसी मद के मूल्यांकन या दायित्व की किसी ऐसी मद के अवधारण के संबंध में उचित समझे और ऐसी सलाह प्राप्त करने की लागत अंतरक बैंक की आस्तियों से पूर्ण रूप में संदेय होगी।

(iv) पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार आस्ति का मूल्यांकन और दायित्वों का अवधारण बैंक और इसके सदस्य और उसके लेनदारों दोनों पर आबद्धकर होगा।

### अध्याय 3

#### लेनदारों और निक्षेपकर्ताओं को संदाय

5. अंतरक बैंक के दायित्व का उन्मोचन :

अंतरिती बैंक को अंतरक बैंक की संपत्ति एवं आस्तियों के अंतरण के प्रतिफल स्वरूप अंतरिती बैंक इसमें तथा निम्नलिखित खण्डों में उल्लिखित अंतरक बैंक की देयताओं का निर्वाह करेगा, यथा :

(क) अंतरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा उस बैंक में कर्मचारीवृन्द प्रतिभूति के रूप में जमा राशि को विहित तारीख तक उस पर उपगत पूर्ण ब्याज यदि कोई हो, का संदाय किया जायेगा या उसका उपबंध किया जायेगा।

#### स्पष्टीकरण

इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ विहित तारीख तक किसी निक्षेप पर देय ब्याज संबंधित निक्षेप का हिस्सा माना जायेगा।

(ख) अंतरक बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते में जिसमें सावधि निक्षेप, रोकड़ प्रमाणपत्र, मासिक निक्षेप, मांग पर या अल्प सूचना पर संदेय निक्षेप या कोई अन्य निक्षेप, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो तथा इस स्कीम के अंतर्गत देय ब्याज सहित वह प्रत्येक खाता जो खण्ड (क) में शामिल न हो, अंतरिती बैंक, विहित तारीख को, अपने धारक (कों) के नाम तत्समान और वैसा ही खाता खोलेगा और उसमें विहित तारीख को इस स्कीम के लिए पैरा (4) में मूल्यांकित आस्तियों में से प्रत्येक खाते के संबंध में उपलब्ध समानुपाती शेयर जमा करेगा, परंतु ऐसा करते समय इस तरह मूल्यांकित आस्तियों में से तत्काल न वसूले जा सकने वाले अग्रिमों को अथवा अशोध्य अथवा संदिग्ध वसूली वाले अग्रिमों को, किसी ऐसी आस्ति अथवा आस्ति के अंश को जिसका विहित तारीख को मूल्यांकन न किया गया हो अथवा उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित प्रयोजनों अथवा अदायगियों के लिए अपेक्षित कोई राशि निकाल दी जाएगी और इस तरह मूल्यांकित आस्ति में अंतरक बैंक को जारी 30 सितम्बर 1996 के अधिस्थगन आदेश के पैरा 2 के खंड (क) (1) के अनुसार की गयी अदायगियों की कुल राशि जोड़ दी जाएगी।

परंतु यह कि विहित तारीख के पहले और 30 सितम्बर 1996 को कारोबार की समाप्ति के बाद अथवा तक किसी निक्षेप खाते से की गयी कोई अदायगी इस उप-पैरा के अंतर्गत जमा राशि के तहत गिनी जाएगी और तदनुसार जमा की जानेवाली राशि ऐसी अदायगी की राशि घटाने के बाद समानुपाती शेयर की राशि होगी।

परंतु यह और कि अंतरिती बैंक किसी विशिष्ट खाते में की गई प्रविष्टि की शुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका करता है तो रिजर्व बैंक के अनुमोदन से उपर्युक्त खंड (ख) के अनुसार उस खाते में की जाने वाली जमा को तब तक रोक रखेगा जब तक कि अंतरिती बैंक ऐसे खाते की शेष राशि अभिनिश्चित नहीं कर लेता।

#### स्पष्टीकरण

"समानुपाती" शब्द, जहां तक यह इस पैरा में आता है, का अभिप्राय होगा विहित तारीख से तुरंत पहले की तारीख तक देय ब्याज सहित 30-9-1996 को कारोबार की समाप्ति पर देय संबंधित शेष राशि के अनुपात में और जहां तक यह इस स्कीम में अन्यत्र कहीं आता है उसका अभिप्राय होगा "अदायगी अथवा वितरण के समय देय संबंधित शेष राशि के अनुपात में"।

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित जमा लिखने के पश्चात्, अंतरिती बैंक न्यूनतम विलंब के साथ किसी हालत में विहित तारीख से

तीन माह से पहले निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित) उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का हर तरह से पालन करते हुए एक सूची प्रस्तुत करेगा और उसके बाद जब भी उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में उल्लिखित राशि निगम से प्राप्त होगी तब अंतरिती बैंक उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अनुसार उस खाते में देय राशि को, राशि प्राप्त होने की तारीख अथवा तारीखों से सात दिन के भीतर, उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक खाते में जमा करेगा।

परंतु—

(i) यदि उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित कोई खाता बंद कर दिया गया है अथवा अदायगी के लिए उस समय परिपक्व हो गया है जिस समय निगम से उस खाते में जमा करने के लिए कोई राशि प्राप्त होती है, तो उस राशि के हकदार व्यक्ति को अंतरिती बैंक द्वारा नकद राशि में भुगतान किया जायेगा;

(ii) यदि उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी राशि के हकदार व्यक्ति का पता नहीं लगता है अथवा वह तत्काल नहीं मिल पाता है तो ऐसे व्यक्ति को देय राशि का प्रावधान किया जायेगा तथा निगम की बहियों में ही अलग से उसे दर्ज किया जायेगा और निगम के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अंतरिती बैंक को उस राशि की अदायगी करे जब तक कि उस राशि के हकदार व्यक्ति का पता न लग जाये अथवा वह मिल न जाये और निगम ने अंतरिती बैंक के माध्यम से उस व्यक्ति से संबंधित अदायगी करने का निर्णय न ले लिया हो।

#### अध्याय 4

6. अंतरक बैंक के सदस्यों के अधिकार और दायित्व :

निर्धारित तारीख को अंतरक बैंक की संपूर्ण समादत्त पूंजी और आरक्षित राशि को डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों और अंतरक बैंक की अन्य आस्तियों के अवक्षयन के लिए उपबंध समझा जाएगा तथा अंतरक बैंक के सदस्यों के अधिकार अंतरिती बैंक के संबंध में निम्नानुसार निर्धारित किये जायेंगे :

निम्नलिखित के संबंध में—

(अ) पिछले पैराग्राफ के खंड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक खाते में, उक्त खाते में शेष राशि, यदि कोई है, उक्त खंड और खंड (ग) के अनुसार जमा नहीं की जायेगी; और

(आ) अंतरक बैंक के प्रत्येक शेयर की बाबत, ऐसी राशि जो नीचे खंड (i) के अनुसरण में अंतरिती बैंक द्वारा विहित तारीख के ठीक पूर्व और/या मांग पर खाते में संदत्त राशि पर, प्रत्येक शेयर धारक द्वारा या उसकी (उनकी) ओर से शेयर पूंजी में सभादत्त समझी गई थी,

संग्रहण खाता समझा जाएगा और उसे अंतरिती बैंक की लेखा बहियों में उस रूप में प्रविष्टि किया जाएगा और उसका खाते से निम्नलिखित ढंग से भुगतान किया जाएगा, अर्थात् :

(:)(क) अंतरिती बैंक, प्रथमतः ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो विहित तारीख को, अंतरक बैंक के आस्थगित शेयर के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत

था (या वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र रहा है) ऐसी तारीख या तारीखों से जो विहित की जाएं, तीन मास की अवधि के भीतर ऐसे शेयर या शेयरों की बाबत उसके द्वारा असंदत्त बकाया न मांगी गई राशि था और बकाया मांगी गई राशि का यदि कोई हो, संदाय करने के लिए कहेगा। और उसके पश्चात् यदि वह आवश्यक पाया जाता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो विहित तारीख को अंतरक बैंक के किसी साधारण शेयर के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था (या इस रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र रहा है) ऐसी तारीख से या तारीखों से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसे शेयर या शेयरों या मांगे गए अतिशेष, यदि कोई हो, की बाबत उसके द्वारा असंदत्त अतिशेष का संदाय करने के लिए कहा जाएगा।

(ख) अंतरिती बैंक मांग के प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त कदम उठाएगा और ऊपर खंड (क) की देय राशियों का, व्यक्तिगत की अवधि के लिए उस पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित संदाय कराएगा;

(ii) अंतरिती बैंक अग्रिमों, क्रय किये गये और भुनाये गये बिलों, बही ऋणों और अन्यान्य ऋणों और अन्य आस्तियों की बाबत, जिन्हें तुरंत वसूल न किए जा सकने वाले और/या वसूली के लिए डूबे हुए या संदेहास्पद अग्रिम समझा गया है या जिन्हें उपर्युक्त पैराग्राफ (4) के अनुसार विहित तारीख के पश्चात् पूर्णतः या भागतः वसूल किया जा सकता है, मांग की प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी उपलब्ध कदम उठाएगा और उसका संदाय कराएगा परंतु यदि ऋण या आस्ति की राशि 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो अंतरिती बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना,

(क) किसी लेनदार या किसी अन्य व्यक्ति से कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा अथवा किसी ऐसे ऋण या आस्ति को अपलिखित नहीं करेगा;

(ख) उसको अन्तरित किसी प्रतिभूति या उसके द्वारा अधिग्रहण की गई आस्ति या विक्रय या अन्यथा निपटान नहीं करेगा।

(iii) अन्तरिती बैंक मांग के प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसके अतिरिक्त सभी उपलब्ध कदम उठाएगा और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 45 एल और धारा 543 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 एच के अधीन अंतरक बैंक के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा नुकसानी के रूप में अधिनिर्णीत राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा।

(iv) अंतरिती बैंक उपर्युक्त खंड (i) (ii) और (iii) में वर्णित मदों के कारण प्रभावित हुई वसूली में से भुगतान करेगा या उक्त राशि अपर्याप्त समझी जाती है तो पैराग्राफ (5) क के अंतर्गत उसके लिए किये गये प्रावधान की सीमा तक किसी भी आकास्मिक देयता के संबंध में तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किसी भी देयता के संबंध में चाहे वह आकास्मिक हो या अत्यांतिक जिसका उपर्युक्त पैराग्राफ (4) के अनुसार निर्धारण नहीं किया गया था और जो निर्धारित तारीख को या उसके बाद सामने आयी अथवा पता लगायी गया थी, प्रावधान करेगा;



(v) अंतरिती बैंक उपर्युक्त खंड (i) (ii) और (iii) में वर्णित मदों के कारण प्रभावित हुई वसूली में से उक्त प्रयोजन के लिए उपगत व्यय उसमें से काटने के बाद और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे अन्य व्ययों का जो उपर्युक्त खंड (iv) के अनुसार उपयुक्त समझे जाते हैं और उक्त राशि उसमें से समायोजित की जाती है, या शेष राशि में से, यदि कोई है, जो इस योजना के प्रयोजन के लिए हिस्सा में लिये गये अनुसार आकस्मिक देयताओं के संबंध में ऐसी देयताओं के अंतिम रूप से पता लगने तक की स्थिति के बाद किये गये प्रावधान में से उपलब्ध होने वाली राशि में से, संदाय करेगा।

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत निगम से अंतरिती बैंक द्वारा प्राप्त की गयी राशि और निगम द्वारा प्रावधान की गयी राशि, यदि कोई है, निगम को अदा की जाये, और

(ख) जमाकर्ताओं के मामले में जिनके संबंध में निगम से अंतरिती बैंक द्वारा राशियां प्राप्त की गयी हैं, वसूली खातों के संबंध में देय राशियां अदा की जायें, और जमाकर्ताओं के मामले में जिनके संबंध में निगम से अंतरिती बैंक द्वारा कोई राशियां प्राप्त की गयी हैं या निगम द्वारा उसके लिये प्रावधान किया गया है संबंधित शेष राशि यदि कोई उनके वसूली खातों में उनको देय है तो निगम द्वारा किये गये भुगतान या प्रावधान के संबंध में निगम को संबंधित खातों से देय राशियों के बाद उपर्युक्त उपखंड (क) के प्रावधानों के अनुसरण में पहले अदा की जाये;

परन्तु निगम को देय राशि का, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, अंतरिती बैंक की बहियों में प्रावधान किया जाये और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 22 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से उक्त राशि निगम को अदा की जाये;

परन्तु इसके अलावा अंतरिती बैंक उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित भुगतान करेगा,

(i) यदि पैराग्राफ (5) के खंड (ख) में उल्लिखित तत्समान या समान खाता बंद नहीं किया गया है या भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, उक्त खाते में राशि जमा करके, और

(ii) यदि संबंधित खाता बंद कर दिया गया है या भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है, नकद राशि में।

(vi) उपर्युक्त खंड (v) के उप खंड (क) के अनुसार निगम को देय राशियों और उक्त खंड के उप खंड (ख) के अनुसार जमाकर्ताओं के वसूली खातों में देय राशियों को उनके बीच समान रैंक दिया जाये और यदि उन्हें पूरा अदा नहीं किया जा सकता है तो उन्हें समान अनुपात में काटा जाये;

(vii) इस पैराग्राफ के खंड (v) में उल्लिखित किये गये पूर्ण भुगतानों या प्रावधानों के बाद अंतरिती बैंक अपने पास उपलब्ध खंड (v) में उल्लिखित राशियों के शेष में से उन राशियों के लिए, यदि कोई है, यथानुपात भुगतान करेगा जो नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से और सीमा तक अंतरक बैंक के पूर्व शेयरधारकों के खातों में देय है :

(क) प्रथमतः अंतरक बैंक के पूर्व अधिमान शेयर धारकों के खातों में देय रकम यदि कोई हो, सभी खातों में पूर्ण संदाय किये जाने तक संदाय करेगा;

(ख) दूसरे अंतरक बैंक के पूर्व साधारण शेयर धारकों के खातों में देय रकम, यदि कोई हो, सभी खातों में पूर्ण संदाय किये जाने तक संदाय करेगा; और उसके बाद

(ग) तीसरे अंतरक बैंक के पूर्व आस्थगित शेयर धारकों के खातों में देय रकम, यदि कोई हो, सभी खातों में पूर्ण संदाय किये जाने तक संदाय करेगा;

(घ) ऊपर उपखंड (क), (ख) और (ग) में वर्णित सारी रकमों का संदाय पूर्ण रूप से कर दिये जाने पर, अंतरिती बैंक के हाथों में बचे हुए अधिशेषों को यदि कोई हो, अंतरक बैंक के पूर्व साधारण शेयर धारकों के बीच यथानुपात वितरित किया जायेगा;

(ङ) परन्तु यदि कोई प्रश्न उठता है कि ऊपर के किसी भी उपखंडों में वर्णित खातों में क्या कोई राशि देय है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय के लिए निर्देशित किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(viii) इस पैरा में निर्दिष्ट संग्रहण खातों की देय रकम इस योजना में उपबंधित की गई सीमा तक केवल अंतरिती बैंक का दायित्व समझी जायेगी।

(ix) इस प्रयोजन के लिए विहित तारीख से बारह वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या ऐसी पूर्वतर अवधि जिसे केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट करे इस पैराग्राफ के खंड (ii) में निर्दिष्ट कोई भी मद जिसकी उस तारीख तक वसूली नहीं की गई है, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अंतरिती बैंक द्वारा मूल्य निकाला जायेगा और अंतरिती बैंक इस पैराग्राफ के खंड (iv) में निर्दिष्ट देयताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी ऐसी रकम से पहले कटौती करने के पश्चात् उस मूल्यंकन को ध्यान में रखते हुए किसी रकम या रकमों के वितरण को अवधारित करेगा जो उपर्युक्त खंडों (v), (vi) और (vii) में उपबंधित क्रम में और रीति से उस तारीख तक समाधान हुए बिना रहा हो, अवधारित की गई किसी रकम/रकमों का वितरण करेगा।

(x) अंतरिती बैंक पूर्वगत खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित मदों की वजह से प्राप्त ऐसे धन को, जिसकी उसके अपने पास अथवा किसी अन्य बैंक या बैंकों के पास रखी ब्याजी जमा राशियों में तत्काल अदायगी की आवश्यकता न हो, को इस प्रकार और ऐसी अवधि के लिए जैसा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार ठीक हो या जैसा भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश दे, उसके अनुसार निवेश करेगा। इससे उपचित ब्याज का उपयोग खंड (iv), (v), (vi) और (vii) में संदर्भित देयताओं को पूरा करने के लिए उसमें दिये गये ढंग से किया जायेगा।

(xi) किसी संविदा में निहित, व्यक्त या समाविष्ट किसी बात के अन्यथा होते हुए भी पैराग्राफ (5) के अनुसार अंतरिती बैंक के पास खोले गये नये खातों के संबंध में ब्याज अदा किया जाये और उसे उक्त के या आगे आनेवाले पैराग्राफ के प्रावधानों के अनुसरण में और अंतरिती बैंक द्वारा यथा अनुमत दरों पर जमा किया जाये।

(xii) अंतरक बैंक का कोई भी जमाकर्ता या अन्य उधारकर्ता इस स्कीम द्वारा निर्धारित सीमा को छोड़कर उसके प्रति अंतरक बैंक की किसी भी देयता के संबंध में अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक के विरुद्ध कोई भी मांग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

883-61/97-2

**अध्याय 5**

अन्तरक बैंक के कर्मचारियों के अधिकार और बाध्यताएं :

7. कर्मचारियों की सेवा का बने रहना :

(1) अन्तरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और अन्तरिती बैंक में उन्हीं पारिश्रमिक तथा सेवा की उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे जो 30 सितम्बर 1996 को कारबार बंद होने के ठीक पहले ऐसे कर्मचारियों के लिए लागू थी।

परन्तु अन्तरक बैंक के उन कर्मचारियों द्वारा जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के द्वारा मंजूर की गई योजना के ठीक पश्चात् की तारीख के एक मास की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय अन्तरिती बैंक या अन्तरक बैंक को लिखित में दी गई सूचना के द्वारा अन्तरिती बैंक के कर्मचारी न बनने के आशय की सूचना दी गई हो, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंध के अधीन और ऐसी पेंशन उपदान, भविष्य निधि और अन्य सेवा निवृत्ति फायदे जो 30 सितम्बर 1996 को कारबार बंद होने के ठीक पहले यथा प्रवृत्त थे, अन्तरिती बैंक के प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिकर के जो साधारणतया अनुज्ञेय हों, संदाय के लिए हकदार होंगे।

(2) परन्तु इसके अलावा अन्तरिती बैंक के उन कर्मचारियों की बात अन्तरिती बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया समझा गया है, अन्तरिती बैंक की सेवा में रहकर उनकी छंटनी किए जाने की दशा में उनके लिए छंटनी प्रतिकर का दायित्व अन्तरिती बैंक द्वारा इस आधार पर किया गया समझा जाएगा कि उनकी सेवाएं निरंतर रही हों और अन्तरिती बैंक को उनके स्थानांतरण द्वारा अवरोधित न की गई हों।

(3) अन्तरिती बैंक उस तारीख से, जिसको स्कीम की मंजूरी दी गई है, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, अन्तरक बैंक के कर्मचारियों को सेवा के उन्हीं पारिश्रमिक और निबंधनों एवं शर्तों के जो अन्तरिती बैंक के तत्समान बैंक और प्रावस्थिति के कर्मचारियों पर लागू होती है, अन्तरक बैंक के उक्त कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव एक समान होने की दशा में या अन्तरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों को अर्हताएं एवं अनुभव के समतुल्य होने पर संदाय करेगा,

परन्तु इस संबंध में कोई संदेह या मतभेद उत्पन्न होता है कि क्या उक्त कर्मचारियों की अर्हता या अनुभव अन्तरिती बैंक के तत्समान बैंक या प्रावस्थिति के अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव समान हैं या उसके समतुल्य हैं या इस संबंध में अन्तरिती बैंक के वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों की प्रक्रिया के संबंध में संदेह और मतभेद भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(4) यथास्थिति अन्तरक बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी भविष्य निधि और/या उपदान निधि के न्यासियों या प्रशासकों, अन्तरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि और/या उपदान निधि के न्यासियों का अन्तरक बैंक यथाशीघ्र विहित तारीख को या इसके पश्चात् या अन्यथा अन्तरिती बैंक के, अन्तरक बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में रखे गए सभी धन और विनिधान को अन्तरित करेगा।

परन्तु पश्चात् कथित ऐसे न्यासी विनिधान के मूल्य में किसी कमी या किसी कार्य की बाबत उपेक्षा या निर्धारित तारीख से पहले किए गए व्यतिक्रम के लिए दायी नहीं होंगे।

**अध्याय 6****प्रकीर्ण**

8. लेनदारों द्वारा मांग अन्तरक बैंक का कोई लेनदार अन्तरक बैंक के या अन्तरिती बैंक के विरुद्ध कोई मांग करने के लिए या इस स्कीम द्वारा विहित सीमा के सिवाय अन्तरक बैंक उसके किसी भी दायित्व की बाबत मांग करने का हकदार नहीं होगा।

9. केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, अन्तरिती या अन्तरक बैंक के विरुद्ध विधि कार्यवाही इस स्कीम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात करने के आशयित किसी बात के लिए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या अन्तरिती या अन्तरक बैंक के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं ही जाएगी।

10. अन्तरक बैंक की शाखाओं का पुनर्गठन : अन्तरिती बैंक अपनी सुविधानुसार अन्तरक बैंक की शाखाओं को एकीकृत करने और/या बन्द करने या वर्तमान हानि उठानेवाली शाखाओं का स्थानांतरण करने का विकल्प रखेगा। तथापि, पूर्वोक्त विकल्प का एक वर्ष की अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से अन्तरिती बैंक द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

11. विवरणियों और जानकारी का दिया जाना : अन्तरिती बैंक इस स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी विवरणियों और सूचना को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।

12. अन्तरक बैंक के शेयरधारकों को सूचना देना : अन्तरिती बैंक अन्तरक बैंक के शेयरधारकों को ऐसे फार्म और ऐसे आवधिक अंतरालों पर, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में विनिर्दिष्ट करेगा, अन्तरक बैंक के कार्यकलापों का एक विवरण प्रस्तुत करेगा। ऐसे विवरणों का प्रेषण रिजर्व बैंक के आदेश देने पर बंद कर दिया जाएगा।

13. नोटिस की तामील की रीति अन्तरिती बैंक द्वारा दिए जाने वाले नोटिस या अन्य संसूचना को, यदि अन्तरक बैंक की बही में लिखे गए पते पर सम्बोधित और पाने वाले को पूर्व संदत्त साधारण डाक द्वारा भेजा गया है तो सम्यक् रूप से तामील किया गया या भेजा गया समझा जायेगा जब तक कि अन्तरिती बैंक की बही में नया पता प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता है और ऐसी नोटिस को इसके डाक में डालने के पश्चात् अड़तालीस घंटों की समाप्ति पर तामील किया हुआ समझा जायेगा। कोई नोटिस या संसूचना जो साधारण हित की है, को एक या एक से अधिक दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा जो उस स्थान पर जहां अन्तरक बैंक अपना कारोबार कर रहा था, परिचालन में हो।

14. इस स्कीम के प्रावधानों की व्यवस्था : यदि इस स्कीम के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो तो मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जायेगा और इसका अभिमत अन्तरिती और अन्तरक दोनों बैंकों के लिए इन दोनों में से प्रत्येक बैंक के सभी सदस्यों, जमाकर्ताओं तथा अन्य लेनदारों एवं इन दोनों में से

प्रत्येक के कर्मचारियों एवं इन दोनों में से प्रत्येक बैंक के संबंध में कोई अधिकार अथवा देयता रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

15. इस स्कीम के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधिकार:— यदि इस स्कीम को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो केन्द्रीय सरकार जैसा केन्द्रीय सरकार समझेगी भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, अंतरक एवं अंतरिती बैंक को अथवा दोनों में से किसी एक को ऐसे निर्देश जारी करेगी जो इस स्कीम से असम्बद्ध नहीं होंगे और कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक अथवा उपयुक्त होंगे।

[ एफ. सं. 17/14/96-बी. ओ. ए. (i) ]

एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Banking Division

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1997

**S.O. 301(E).**—Whereas on an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government has made, an order of incorporation in respect of the Punjab Co-operative Bank Ltd., Amritsar under sub-section (2) of the said section;

And, whereas the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 45 of the said Act has prepared a scheme for the amalgamation of the Punjab Co-operative Bank Ltd. with Oriental Bank of Commerce;

And, whereas the Reserve Bank of India after having sent the said scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said scheme had modified that scheme and forwarded it to the Central Government for sanction;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions the scheme on and subject to the terms and conditions hereinafter mentioned.

## CHAPTER I

### Preliminary

1. Short title and commencement :—(1) This Scheme may be called the Punjab Co-operative Bank Ltd. (Amalgamation with Oriental Bank of Commerce) Scheme, 1997.

(2) It shall come into force on such date (hereinafter referred to as the prescribed date) as the Central Government may, by notification in the Official Gazette specify.

## Chapter II

### Transfer of business, properties, assets and liabilities

2. Transfer of assets and liabilities and general effect thereof :—(1) As on and from the prescribed date all rights, powers, claims, demands, interests, authorities, privileges, benefits, assets and properties of the transferor bank, movable and immovable, including premises subject to all incidents of tenure and to the rents and other sums of money and covenants reserved by or contained in the leases or agreements under which they are held, office furniture, loose equipment, plant apparatus and appliances, books, papers, stocks of stationery, other stock and stores, all investments in stocks, shares and securities, all bills receivable in hand and in transit, all cash in hand and on current or deposit account (including money at call or short notice) with banks bullion, all book debts, mortgage debts and other debts with the benefit of securities, or any guarantee therefor, all other if any, property rights and assets benefit of all guarantees in connection with the business of the transferor bank, shall, subject to the other provisions of this scheme, stand transferred to, and become the properties and assets of, the transferee bank; and as from the prescribed date all the liabilities, duties and obligations of the transferor bank shall be and shall become the liabilities, duties and obligations of the transferee bank to the extent and in the matter provided hereinafter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank the transferee bank had been a party thereto, or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

(3) If on the prescribed date any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the transferor bank is pending; the same shall not abate, or be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall subject to the other provisions of this scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank.

(4) If according to the laws of any country outside India the provisions of this scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such assets or liability shall, on the prescribed date, stand entrusted to the Chief Executive Officer for the time being of the transferee bank and the Chief Executive Officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively winding up its



affairs. The Chief Executive Officer shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith the Chief Executive Officer may, either himself or through any person authorised by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

3 Closure of books of the transferor bank and preparation of balance sheet :—(1) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance sheets prepared in the first instance as at the close of business on the 30th September, 1996 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the prescribed date and the balance sheets shall be got audited and certified by a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants approved or nominated by the Reserve Bank of India for the purpose.

(2) A copy each of the balance sheet of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing paragraph, shall be filed by the transferor bank with the Registrar of Companies as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance sheets or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the Registrar of Companies or to hold any annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 1956, and it shall not thereafter be necessary for the Board of Directors of the transferor bank to meet as required by Section 285 of that Act.

4. Valuation of assets and determination of liabilities :—The transferee bank shall, in consultation with the transferor bank, value the property and assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely,—

(1)(a) investments other than Government Securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the prescribed date.

(b)(i) Government Securities shall be valued as on the day immediately preceding the prescribed date in accordance with the principles laid down in the notification issued by Reserve Bank of India for the purpose of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949.

(ii) The Securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher.

(iii) Where the market value of any Government security such as the Zamindari Abolition Bonds or other similar security in respect of which the principal is payable in

instalments is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such an amount as is considered reasonable having regard to the instalments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such instalments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors.

(c) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period.

(d) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not ascertainable only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors.

(e) Premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value.

(f) Furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realisable value as may be considered reasonable.

(g) Advances including bills purchased and discounted, book debts and sundry assets, will be scrutinised by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefor examined and verified by the transferee bank. Thereafter the advances, including portions thereof, will be classified into two categories namely, "Advances considered good and readily realisable" and "Advances considered not readily realisable and/or bad and doubtful of recovery".

(2) Liabilities for purposes of this scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date.

(3)(i) Where the valuation of any asset cannot be determined on the prescribed date, it may, with the approval of the Reserve bank of India be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date.

(ii) In the event of any disagreement between the transferee bank and the transferor bank as regards the valuation of any asset and/or the classification of any advance and/or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India, whose opinion shall be final, provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of this scheme.

(iii) It shall be competent for the Reserve Bank of In-



dia in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

(iv) The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on both the banks and the members and creditors thereof.

### Chapter III

Payment to creditors and depositors.

5. Discharge of liability of the transferor bank:

In consideration of the transfer of the property and the assets of the transferor bank to the transferee bank, the transferee bank shall discharge the liabilities of the transferor bank to the extent mentioned in this and the following clauses, namely :

(a) Any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits together with interest, if any, accrued thereon upto the prescribed date and all other outside liabilities as on the prescribed date excluding deposits shall be paid or provided for in full.

#### Explanation

For the purpose of this sub-paragraph, interest payable on a deposit upto the prescribed date shall be regarded as part of the concerned deposit.

(b) In respect of every savings bank account or current account of any other deposit including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposit by whatever name called with the transferor bank and every other account not covered by Clause (a) including interest to the extent payable under this scheme, the transferee bank shall open with itself on the prescribed date a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto the pro rata share available in respect of each of the accounts out of the assets referred to in paragraph (4) as valued for the purposes of this scheme on the prescribed date, after excluding from the said assets as so valued the advances considered not readily realisable or bad or doubtful of recovery, any asset or portion of an asset not valued on the prescribed date and any amount needed for the payments or provisions mentioned at Clause (a) above and after adding to the said assets as so valued the aggregate amount of the payments made in terms of clause (a) (i) of paragraph 2 of the moratorium order dated the 30 September, 1996 issued to the transferor bank.

Provided that any payment made from a deposit account on, or after the close of business on 30 September

1996 and before the prescribed date, shall be reckoned towards the amount to be credited under this sub-paragraph and, accordingly the amount to be credited shall be the pro rata share less the amount of such payment.

Provided further that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account it may with the approval of the Reserve Bank, withhold the credit to be made in that account in terms of clause (b) above till the transferee bank is able to ascertain the correct balance in such account.

#### Explanation

The term 'pro rata' shall, insofar as it occurs in this paragraph, mean in proportion to the respective amounts remaining due as at the close of business on the 30th September 1996 together with the interest payable upto the date immediately preceding the prescribed date and shall, insofar as it occurs elsewhere in this scheme, 'mean in proportion to the respective amounts remaining due at the time of the payment or distribution'

(c) After the credits referred to in clause (b) above have been afforded, the transferee bank shall, with the least possible delay but in any case not later than three months from the prescribed date, furnish to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (hereinafter referred to as the Corporation) a list complying in all respects with the requirements of sub-section (1) of section 18 of the Act and thereafter whenever amounts referred to in sub-section (2) of section 18 of that Act are received from the Corporation, the transferee bank shall credit each of the accounts referred to in clause (b) above, within seven days from the date or dates on which the amounts are received, to the extent of the sums due to that account in accordance with sub-section (2) of section 18 of that Act :

Provided that--

(i) If any account referred to in clause (b) above has been closed or has matured for payment at the time when any amount for credit to that account is received from the Corporation, the payment to the person entitled to the said amount shall be made by the transferee bank in cash;

(ii) In case the person entitled to any amount referred to in clause (b) above cannot be found or is not readily traceable, provision for the amount due to such person shall be made and accounted for separately on the books of the Corporation itself and it shall not be necessary for the Corporation to pay the amounts to the transferee bank unless the person entitled to the amount is found or traced and the Corporation has decided to make the payment in respect of that person through the transferee bank.

### Chapter IV

6. Rights and liabilities of the members of the transferor

883-91/97-3

On the prescribed date, the entire amount of the paid-up capital and reserves of the transferor bank shall be treated as provision for bad and doubtful debts and depreciation in other assets of the transferor bank and the rights of the members of the transferor bank shall, in relation to the transferee bank, be as provided for as below :

In respect of —

(A) every account mentioned in clause (b) of the preceding paragraph, the balance in the account, if any, remaining uncredited in terms of that clause and clause (c); and

(B) every share in the transferor bank, the amount of which was treated as paid-up towards share capital by or on behalf of each shareholder immediately before the prescribed date and/or the amount and on account of the calls made by the transferee bank in pursuance of clause (i) below.

shall be treated as a collection account and shall be entered as such in the books of the transferee bank and payments against the account shall be made in the following manner, namely:

(i) (a) the transferee bank shall, in the first instance, call upon every person who on the prescribed date was registered as the holder of a deferred share in the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares and the calls in arrears, if any, and thereafter, if it is found to be so necessary, every person who was, as on the prescribed date, registered as the holder of an ordinary share of the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares or the calls in arrears, if any;

(b) the transferee bank shall take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts due under clause (a) above together with interest at six per cent per annum for the period of the default;

(ii) the transferee bank shall in respect of the advance, bills purchased and discounted, book debts and sundry debts and other assets, which are classified as "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery," or which are or may be realisable wholly or partly after the prescribed date in terms of paragraph (4) above, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce payment, provided, however, that if the amount of a debt or asset exceeds Rs. 50,000, the transferee bank shall not except with the approval of the Reserve Bank of India,

(a) enter into a compromise or arrangement with the debtor or any other person or write off any such debt or asset;

(b) sell or otherwise dispose of any securities transferred to it or any asset taken over by it.

(iii) the transferee bank shall in addition take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts, if any, awarded as damages by the High Court against any promoter, director, manager or other officer of the transferor bank under Section 45L of the Banking Regulation Act, 1949, read with Section 45H thereof and also with Section 543 of the Companies Act, 1956;

(iv) the transferee bank may, out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above, make payment or provision in respect of any contingent liability to the extent that the provision made thereof under paragraph (5)(a) proves to be inadequate, as also with the prior approval of the Reserve Bank, in respect of any liability whether contingent or absolute which was not assessed in terms of paragraph (4) above and has arisen or been discovered on or after the prescribed date;

(v) the transferee bank shall out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above, after deducting therefrom the expenditure incurred for the purpose and, with the approval of the Reserve Bank of India, such other expenses as may be considered reasonable and the amount appropriated therefrom in terms of clause (iv) above, or out of the balance, if any, which may be available from out of the provision in respect of contingent liabilities as reckoned for the purpose of this scheme after the extent of such liabilities has finally been ascertained.

(a) pay to the Corporation the amount received by the transferee bank from the Corporation under sub-section (2) of Section 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, and the amount, if any, provided for by the Corporation, and

(b) pay in the case of depositors in respect of whom the amounts have been received by the transferee bank from the Corporation, the amounts due in respect of the collection accounts, and in the case of depositors in respect of whom any amounts have been received by the transferee bank from the Corporation or have been provided for by the Corporation the balance if any due to them in their collection accounts after the amounts due from the said accounts to the Corporation in respect of the payment made or provided for by the Corporation have first been paid in accordance with the provisions of Sub-clause (a) above :

Provided that the amount due to the Corporation shall, if it becomes necessary so to do, be provided for in the books of the transferee bank and be paid to the Corporation in the manner specified in clause (b) of regulation 22 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961;

Provided further that the transferee bank shall; make the payments referred to in clause (b) above,

(i) if the corresponding or similar account mentioned in clause (b) of paragraph (5) has not been closed or has not matured for payment, by credit to that account, and

(ii) if the said account has been closed or has matured for payment, in cash.

(vi) The amounts due to the Corporation in terms of sub-clause (a) of clause (v) above and the amounts due to the collection accounts of the depositors in terms of sub-clause (b) of that clause shall rank equally among themselves, and if they cannot be paid in full shall abate in equal proportions;

(vii) After the payments referred to in clause (v) of this paragraph have been made or provided for in full, the transferee bank shall, out of the balance of the amounts referred to in clause (v) which may be available to it, make payments *pro rata* towards the amounts, if any, due to the accounts of the former shareholders of the transferor bank in the manner and to the extent specified below :

- (a) in the first place, the amounts if any, due to the accounts of the former preference shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;
- (b) in the second place, the amounts, if any, due to the accounts of the former ordinary shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made and thereafter;
- (c) in the third place, the amounts, if any, due to the accounts of the former deferred shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;
- (d) after all the amounts mentioned in sub-clauses (a) (b) and (c) above have been paid in full, the surplus, if any, remaining in the hands of the transferee bank shall be distributed *pro rata* among the former ordinary shareholders of the transferor bank.
- (e) provided that if any question arises whether any amounts are due against an account mentioned in any of the above sub-clauses, it shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(viii) the amounts due to the collection accounts referred to in this paragraph shall be deemed to be a liability of the transferee bank only to the extent provided for in this scheme;

(ix) on the expiry of twelve years from the prescribed date or such earlier period as the Central Government after consulting the Reserve Bank of India may specify for this purpose, any item referred to in clause (ii) of this paragraph which may not have been realised by that date shall be valued by the transferee bank in consultation with the Reserve Bank of India and the transferee bank shall distribute any

amount or amounts determined in the light of that valuation after deducting therefrom first any sum necessary for meeting the liabilities referred to in clause (iv) of this paragraph which may remain unsatisfied as on that date in the order and the manner provided in clauses (v), (vi) and (vii) above.

(x) the transferee bank shall invest such moneys realised on account of items mentioned in the preceding clauses (i), (ii) and (iii) as are not likely to be required by it for immediate payment, in interest bearing deposits with itself or with any other bank or banks, in such manner and for such periods as may be appropriate having regard to the facts and circumstances of the case or as the Reserve Bank of India may direct. The interest accrued shall be applied for meeting the liabilities referred to in clauses (iv), (v), (vi) and (vii) in the manner indicated therein.

(xi) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, interest shall be paid in respect of the new accounts opened with the transferee bank in terms of paragraph (5) and credited in accordance with the provisions of that or the next succeeding paragraphs and at such rates as the transferee bank may allow.

(xii) No depositor or other creditors of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by this scheme.

## CHAPTER V

### RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE EMPLOYEES OF TRANSFEROR BANK:

#### 7. Continuation of service of the employees:

(1) All the employees of the transferor bank shall continue in service and be deemed to have been appointed in the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as were applicable to such employees immediately before the close of business on 30th September 1996.

Provided that the employees of the transferor bank who have, by notice in writing given to the transferor or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the date on which this scheme has been sanctioned by the Central Government, intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible under the rules of authorisations of the transferor bank immediately before the close of business on 30th September 1996.

(2) Provided further that the transferee bank shall in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank be deemed also to have taken over the liability for



them of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(3) The transferee bank shall, on the expiry of a period not longer than three years from the date on which this scheme is sanctioned, pay or grant to the employees of the transferor bank the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank.

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure of principles to be adopted for the fixation of the pay of the employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(4) The trustees or administrators of any provident fund and/or gratuity fund constituted for the employees of the transferor bank or as the case may be the transferee bank shall on or as soon as possible after the prescribed date transfer to the trustee of the employees provident fund and/or gratuity fund constituted for the transferee bank, or otherwise as the transferee bank may direct, all the monies and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank.

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect, or default done before the prescribed date.

## CHAPTER VI

### Miscellaneous

**8. Demand by Creditors:** No creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by this scheme.

**9. Legal proceedings against Central Government, Reserve Bank, transferee or the transferor bank:** No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government, the Reserve Bank of India or the transferee or the transferor bank for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this scheme.

**10. Reorganisation of branches of transferor bank:** The transferee bank shall have the option of integrating branches of transferor bank according to its convenience and/or close down or shift the existing loss making branches of the transferor bank. The aforesaid option will, however,

be exercised by the transferee bank with the prior approval of Reserve Bank of India within a period of one year.

**11. Furnishing statements and information:** The transferee bank shall submit to the Reserve Bank of India such statements and information as may be required by the Reserve Bank of India from time to time regarding the implementation of this scheme.

**12. Furnishing information to shareholders of transferor bank:** The transferee bank shall furnish to the shareholders of the transferor bank a statement of affairs of the transferor bank in such form and at such periodical intervals as the Reserve Bank of India may specify in this behalf. The sending of such statements shall be discontinued when so directed by the Reserve Bank.

**13. Manner of service of notice:** Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by pre-paid ordinary post to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank, and such notice shall be deemed to be served on the expiry of forty eight hours after it has been posted. Any notice or communication which is of general interest shall be advertised in addition in one or more daily newspapers which may be in circulation at the places where the transferor bank was transacting its business.

**14. Interpretation of the provision of this scheme:** If any doubt arises in interpreting any of the provisions of this scheme, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India and its opinion shall be conclusive and binding on both the transferee and transferor banks, and also on all the members, depositors and other creditors and employees of each of these banks and on any other person having any rights or liability in relation to any of these banks.

**15. Powers of Central Government for removing the difficulties in giving effect to the provisions of this scheme:** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this scheme, the Central Government may issue to the transferor and the transferee banks or to either of them such directions not inconsistent with this scheme as may appear to the Central Government, after consulting the Reserve Bank of India, to be necessary or appropriate for the purpose of removing the difficulty.

[F. No. 17/14/96-BOA-(i)]

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का. आ. 302(अ).— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949



(1949 का 10) की धारा 45 की उप-धारा (7) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा :—

(क) 8 अप्रैल, 1997 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट करती है जिस तारीख को पंजाब सहकारी बैंक लि. (ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में समामेलन) की योजना, 1997 जो उक्त उप-धारा के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी है, के पैराग्राफ 5 को छोड़कर सभी पैराग्राफ, और

(ख) 8 मई, 1997 उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तारीख को पैराग्राफ 5 लागू होगा।

[एफ. सं. 17/14/96-बी. ओ. ए. (ii)]

एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव

# NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1997

**S.O. 302 (E).**—In pursuance of sub-section (7) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies:—

- (a) the 8th April, 1997 as the date on which all paragraphs, except paragraph 5, and
- (b) the 8th May, 1997 as the date on which paragraph 5,

of the Punjab Co-operative Bank Ltd. (Amalgamation with Oriental Bank of Commerce) Scheme, 1997, which has been sanctioned by the Central Government under the provisions of the said sub-section, shall come into force.

[F. No. 17/14/96-BOA (ii)]

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

883-4(9)-4

